by the Ministry of Railways to have a complete review of the existing facilities available in the railway platforms in Tamil Nadu? May I know from the Minister whether there is any consideration by the Ministry to construct additional platforms wherever necessary and also extend the facilities which were available when the platforms were length-wise short? Now, with the introduction of additional coaches, additional facilities are required now. May I know from the Minister whether there is any consideration for extending the existing facilities which will be corresponding to the length of the platforms? These facilities should be extended to Kodaikanal road, which is a junction, leading to Kodaikanal hills. An identical station can be considered.

SHRI BANDARU DATTATRAYA: Sir, this is an ongoing project. In the Indian Railways, we have an allocation under the head 'Passenger Amenities', under which we are spending Rs. 210 crores for the entire country. Every time, whenever there is need for extension of platforms, these are undertaken from the Passenger Amenities. Regarding Kodaikanal road, I will get the matter examined.

उर्व्रक निर्माताओं को सब्सिडी

*89 **श्री लाजपत रायः**
श्री कपिल सिब्बल :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश मे विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के निर्माताओं को सब्सिडी देने के लिए अलग-अलग प्रणालियां अपनाई हुई है3

(ख) यदि हां, तो उन रासायनिक उर्वरक निर्माताओं का प्रणाली-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें सब्सिडी दी जाती है, और

(ग) इन प्रणालियों को अपनाने से होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) दिनांक 1.4.2003 से लागू हुई नई मूल्य निर्धारण नीति के तहत यूरिया उत्पदकों को राजसहायता दी जा रही है। नई निर्धारण योजना के तहत ग्रुप आधारित रियायत

दरें निर्धारित करने के लिए यूरिया इकाइयों को पुरानेपन (विंटेज) और फीडस्टॉक के आधार पर 6 ग्रुपों में रखा गया है। ये ग्रुप है-1992 से पूर्व की गैस आधारित इकाईयां,1992 के बाद की गैस आधारित इकाईयां,1992 के बाद नैफ्था आधारित इकाईयां, ईधन तेल/निम्न सल्फर हैवी स्टॉक (एफओ/एलएसएचएस) आधारित इकाईयां औरा मिश्रित ऊर्जा आधारित इकाईयां। दिनांक 1.4.2003 से लागू ग्रुप आधारित रियायत की संगणना वर्ष 2002-03 के लिए फीडस्टॉक, ईधन, खरीदी गई बिजली और पानी से संबंधित वृद्वि/कमी के लिए अघतन तथा 1.4.2002 को लागू प्रतिधारण मूल्यों के आधार पर की जाएगी।

नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर राजसहायता रियायत योजना के तहत दी जाती है। सभी उत्पादको के लिए डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी) के लिए रियायत दरें अंतराष्ट्रीय बाजार में आयातित अमोनिया और आयातित फॉस्फोरिक एसिड के प्रचालित मूल्यों को समायोजित करने के पश्चात निकाली जाती है। मिश्रित उर्वरकों के लिए रियायत दरें अंतराष्ट्रीय बाजार के कच्चे मालों, अमोनिया, यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड के प्रचालित मूल्यो और स्वदेंशी बाजार में नैफ्था के प्रचालित मूल्यों पर आधरित पोषकों की लागत को समायोजित करने के पश्चात निकाली जाती है। सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के उत्पादों को राजसहायता समान रूप से 650 रूपये प्रति मी. टन की दर से दी जाती है।

(ख) यूरिया के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना और नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरको के लिए रियायत की दरों का हिसाब लगाने की पद्वति, अधिक पारदर्शिता, दक्षता और समानता सुनिश्चित करने तथा इन उर्वरको के उत्पादकों/आपूर्तिकर्ताओं को उचित मूल्य अनुमत करने के लिए अपनाई गई है।

Subsidy to fertilizer manufacturers

†*89. SHRI LAJPAT RAI:
SHRI KAPIL SIBAL:

Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have adopted different methods for providing subsidy to different kinds of chemical fertilizer manufacturers of the country;

(b) if so, method-wise details of chemical fertilizer manufacturers who are provided with subsidy; and

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) details of the benefit of adopting these methods?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SUKH DEV SINGH DHINDSA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Subsidy to urea manufacturers is being provided under the New Pricing Schemes (NPS) which has come into effect from 1.4.2003. Under the NPS, the urea units have been placed in six groups based on vintage and feedstock, for determining the group based concession rates. These groups are: pre-1992 gas based units, post-1992 gas based units, pre-1992 naphtha based units, post-1992 naphtha based units, Fuel Oil/ Low Sulphur Heavy Stock (FO/LSHS) based units and mixed energy based units.The group based concession rates w.e.f. 1.4.2003 would be computed on the basis of the retention prices applicable as on 1.4.2002 duly updated for escalation/de-escalation in respect of feedstock, fuel, purchased power and water for the year 2002-03.

Subsidy on decontrolled phosphatic and potassic fertilizers is given under the Concession Scheme. The concession rates for di-ammonium phosphate (DAP) are worked out for all the manufacturers after adjusting the imported ammonia and imported phosphoric acid prices prevailing in the international market. Rates of concession for complex fertilizers are worked out after adjusting the nutrients cost based on the raw materials, ammonia, urea, phosphoric acid prices prevailing in the international market and naphtha prices prevailing in the indigenous market. Manufacturers of single super phosphate (SSP) are provided subsidy uniformly at the rate of Rs. 650 per metric ton.

(c) The NPS for urea and the methodology of calculating the rates of concession for decontrolled phosphatic and potassic. fertilizers have been adopted to ensure greater transparency, efficiency and uniformity and to allow fair price to the manufacturers/ suppliers of these fertilizers.

SHRI LAJPAT RAI: Sir, the hon. Minister has stated in the reply tabled in the House that New Pricing Scheme has been introduced from 1st April, 2003. In this connection, I would like to know whether

the Government have calculated the cost of production of each category after the New Pricing Scheme has been enforced. May I know from the Minister what steps have been taken to bring down the production cost of fertilizers so as to minimise the subsidy?

Second part of my question is: whether any irregularities have been noticed in providing fertilizer subsidy and the action taken thereupon during the past three years and whether the culprits of urea scandal in mid-90s have been brought to book?

श्री सुखदेव सिंह ढिंड़सा : सर, मैंने डिटेल में जवाब दिया है कि हमने जो पालिसी बनाई है, वह ग्रुप सिस्टम पर आधारित है और ग्रुप में से ऐवरेज लेकर, यूरिया के लिए पॉलिसी हमने बनाई है। जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें हरेक यूनिट को लेते थे, उससे बड़ी मुस्किल आती थी और इस नई पॉलिसी से ट्रांसपैरेंसी आई है। दूसरा जो इनका सवाल है यूरिया केस के बारे में, वह बड़ा फेमस केस था और वह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। सीबीआई ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और उसका अभी तक कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है, यह कारसन लि. से संबंधित केस था।

श्री लाजपत राय : चेयरमैन साहब, जवाब तो अधूरा है। मैंने पूछा था कि चैक्स क्या

मेरा दूसरा क्वेश्चन है: What is the number of fertilizer manufacturing units in the public sector closed during the last three years? May I know whether any effort has been made by the Government to keep them running by arranging foreign collaboration and allocating quota of imported fertilizer, as has been done in the private sector? The second part of my question is...

श्री सभापति : सैंकिडं पार्ट नहीं होता।

श्री लाजपत राय :इसी का सैकिडं पार्ट है।

श्री सभापति :इसी का सैकिडं पार्ट। आपने 3 तो पहले कर लिए, 3 अब करेंगे तो 6 पार्ट हो जाएंगे।

श्री लाजपत राय :उसी के साथ मिलती बात है।

श्री सभापति : आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, सबको मिलाकर एक ही बात में पूछ लेते है।

श्री लाजपत राय : ठीक है, सर। आप काटा लगा दीजिए।

श्री सुखदेव सिंह ढिंड़सा : सर, जहां तक कम्पनीज बंद होने का सवाल है, तो दो कम्पनीज बंद की है। मैंने पिछले सैशन में भी बताया था कि उनका प्रोडक्शन पहले ही बंद था, इसलिए उसका उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ा है। दूसरा, दो सिक कम्पनीज जो अभी बीआईएफआर में है, उनका फैसला अभी होना है। और कोई कम्पनी बंद नहीं है। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि वर्तमान में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है और 2005 में हमारा एक ज्वाइंट सैक्टर में प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे 16.5 लाख टन यूरिया देश में आएगा। इसके अलावा हमने कोशिश की है और कोआपरेटिव सैक्टर में जो कृभकों का एक प्रोजेक्ट है उसके ऐक्सपेंशन के ऐप्रूवल देने के लिए हम तैयारी कर रहे है।

SHRI KAPIL SIBAL: Mr. Chairman, Sir, we are moving from a regime of individual retention price mechanism to a group-based retention price mechanism. Ever since this subsidy has been granted in this particular sector, we have always been subsidizing the inefficient. Sir, the facts are that 42 per cent of the entire production, which is about 400 lakh tonnes in this sector of fertilizers, is accounted for consumption by small and marginal farmers who own less than two hectares of land. And, if that is the correct position, then it is far better from the costs stand point to give the subsidy directly to the farmer than subsidize the producer.

Has the Government set up a mechanism or has the Government done any exercise to assess whether in switching over direct subsidy to the small and marginal farmers, it will, in fact, cost us less, the subsidy will reach the farmer and we do not have to subsidize the producer who is inefficient.

श्री सुखदेव सिंह ढिंड़सा :सर, जो इनका पहला है वह जो ठीक है। यह नई पॉलिसी इसीलिए बनाई गई है क्योंकि पहले उसका मिस-यूज होता रहा है। इससे एफिसिएंसी आएगी, क्योंकि ग्रुप बेस्ड में जो ऊपर वाले होंगे उसको नीचे आना ही होगा अगर उनको सब्सिडी लेनी है। तो इसी के लिए जो इनएफिसिएंट यूनिट थे उनको इस पॉलिसी में नुकसान होगा उनको अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाना पड़ेगा। दूसरा है, पहले भी बहुत बार डिसकस हुआ है कि बजाए कम्पनीज को देने के डायरेक्टली किसान को दी जाए। लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि यह कैसे होगा क्योंकि लाखो नहीं करोड़ो किसान है और छोटे किसानों को कभी सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन जो बड़ा किसान है वह तो ले जाता है। हमने पिछला तजुर्बा देखा है कि छोआ किसान जो बेचारा गरीब होता है वह ले नही सकता, उसके लिए मुश्किल है। ऑनरेबल मेंबर, अगर ऐसा कोई सजेशन देंगे तो मैं विचार कर सकता हूं।

श्री कपिल सिब्बल :सर, अभी जो मकेनिज्म चल रहा है, आज के दिन pricing is an impossible thing because you are going to calculate the import price in respect of chemical based fertilizers. Import prices will have to be calculated on a monthly basis because the international prices will move. How are you going to do that? How is the system going to work?

MR. CHAIRMAN: Next question.

Progress under 'Sarva Shiksha Abhiyan'

*90. SHRI MURLI DEORA:
SHRI DRUPAD BORGOHAIN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a)whether Ministry's flagship programme 'Sarva Shiksha Abhiyan' has achieved any amount of success;

(b)if so, the details thereof;

(c)the names of the States which are not taking keen interest in the programme and not releasing funds of their share;

(d)the amount granted to each State for 2002-03 and the amount spent by them so far;

(e)whether there is any common standard prescribed to build schools and to supply different materials to the schools in a State; and

(f) how are the propagators of 'Sarva Shiksha Abhiyan' appointed and what is their individual emolument?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. SANJAY PASWAN): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (c) The Government has launched the programme of *Sarva Shiksha Abhiyan* in November. 2000 to achieve the goal of Universalisation of Elementary Education in Mission mode in partnership with States. Out of the 600 districts in the country, District Elementary